Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

सितम्बर 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- अटल आवासीय विद्यालयों का 'गुरुवार्ता संगम' कार्यक्रम 4
- 'बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान-2023' का शुभारंभ 5
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पछाड़ा 7
- उत्तर प्रदेश के तीन शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 8
- प्रदेश के 94 शिक्षकों को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार 9
- नमामि गंगे ने मेरठ में सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये 9
- उत्तर प्रदेश के आठ ज़िले सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट वाले बनेंगे 10
- प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई-बस 11
- उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू होगा ई-ऑफिस 12
- हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, देश में बुलंदशहर पहले व बरेली तीसरे स्थान पर 14
- बुंदेलखंड में बनेगा नोएडा जैसा औद्योगिक शहर 15
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई 16
- लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल 17
- आयुष्मान भव: अभियान 18
- हिन्दी दिवस के अवसर पर 16 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित 19
- आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन की मासिक टॉप और बॉटम 10 ज़िलों की रैंकिंग जारी 19
- उत्तर प्रदेश ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप जीती 20
- मुख्यमंत्री ने गीडा में किया तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन 21
- उत्तर प्रदेश में अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक ज़ोन 22
- बरेली के इत्र से महकेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 23
- लखनऊ की आस्था स्ट्रांग वुमेन और आर्य बने स्ट्रांग मैन 24
- कवि अरुण कमल को मिलेगा 'निराला स्मृति सम्मान' 25
- 20वाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला का लखनऊ में होगा आयोजन 25
- आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ चलाएंगी औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन 26
- उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ 27
- प्रधानमंत्री ने काशी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया 29
- लखनऊ का एबीसी केंद्र बनेगा देश के लिये मॉडल 30
- लखनऊ में होंगे राज्य ओपेन पैरा खेल 31
- लखनऊ की पूर्णिमा को मिला विद्यावती स्मृति सम्मान 32
- मोटोजीपी बाइक रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) ग्रेटर नोएडा में हुई संपन्न 33
- आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को मिले दो अवॉर्ड 35
- स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा स्थान 36
- उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हासिल किया 100% ओडीएफ प्लस कवरेज 38

नोट :

उत्तर प्रदेश

ज़िलों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अब होगी अलग-अलग

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के ज़िलों में अब कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण और समीक्षा अलग-अलग स्तर पर होगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों के विकास कार्य और कानून व्यवस्था में विभिन्न स्तर के अधिकारियों की समीक्षा सीएम डैश बोर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके कार्य में सुधार कराया जाएगा।

- शासन के आदेश के बाद 68 ज़िलों में ज़िलाधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वहीं पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
- मंडल स्तर पर कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा अब अलग-अलग होगी। ज़िलास्तरीय समीक्षा बैठक के एक सप्ताह की अवधि में मंडलस्तरीय बैठक का आयोजन करना होगा।

नोट :

- मंडल स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होगी। जिन मंडल मुख्यालयों पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं हैं, वहाँ पर कानून व्यवस्था की बैठक भी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ही होगी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक एवं मंडल में स्थित ज़िलों के पुलिस कप्तान मौजूद रहेंगे।
- राजस्व और विकास कार्य के लिये मंडल में अपर आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कानून व्यवस्था के लिये मंडल में पुलिस उप महानिरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- ज़िला स्तर पर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग-अलग होगी। विकास कार्य की समीक्षा ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगी। हर महीने सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग प्रकाशन के एक सप्ताह में बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिये गए हैं।
  - ज़िला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिये मुख्य विकास अधिकारी को सीएम डैशबोर्ड का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिन ज़िलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं हैं, वहाँ पर कानून व्यवस्था की समीक्षा ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में की जाएगी। बैठक में एसएसपी, एसपी, एडीएम प्रशासन, एएसपी, डीएसपी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहेंगे।
  - लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, सहित जिन ज़िलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की समीक्षा प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक की ओर से भी हर महीने की जाएगी।
  - जिन ज़िलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, वहाँ कानून व्यवस्था की समीक्षा पुलिस आयुक्त करेंगे। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी और सभी थानाध्यक्ष शामिल रहेंगे।
- सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर हर महीने की 15 तारीख को रैंकिंग जारी की जाएगी। रैंकिंग में परफार्मेंस इंडेक्स, डाटा क्वालिटी इंडेक्स और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर हुए कामकाज को आधार बनाया जाएगा।
- भविष्य में विभागों की ओर से सीएम डैशबोर्ड पर ज़िलास्तरीय अधिकारियों की रैंकिंग के आधार पर मिले गुणांक का प्रयोग मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण में किया जाएगा।

अटल आवासीय विद्यालयों का 'गुरुवार्ता संगम' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में आयोजित अटल आवासीय विद्यालयों का 'गुरुवार्ता संगम' कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय की परिचायिका का विमोचन तथा वेबसाइट को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ इस सत्र में किया जा रहा है। अगले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बचे हुए 57 जनपदों में इसी तर्ज पर एक-एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा
- अटल आवासीय विद्यालय सी.बी.एस.ई. बोर्ड के पैटर्न पर संचालित होंगे। इनमें लॉजिंग, फूडिंग सहित सभी व्यवस्थाएँ होंगी।
- कक्षा-06 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उठाएगा।

- ये संस्थान न केवल वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि भारतीय मूल्यों और गुरुकुल परंपराओं को भी बढ़ावा देंगे, जिससे युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी, जो दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी।
- ये स्कूल न केवल छात्रों के कौशल विकास के केंद्र होंगे, बल्कि राज्य की प्रगति में योगदान देने वाले श्रमिकों, वंचितों और वंचितों के बच्चों के लिये एकीकृत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों के लिये चयनित छात्र-छात्राओं को स्कूल किट वितरित की तथा COVID-19 अवधि के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिये बाल सेवा योजना (बाल कल्याण योजना) शुरू की गई।

'बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान-2023' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 'बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान-2023' का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बी-पैक्स (साधन सहकारी समितियाँ) सदस्यता महाअभियान-2023 (01 से 30 सितंबर, 2023 तक) पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर बी-पैक्स सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिये ऑनलाइन पोर्टल https://wwwpacsmember.in/ और टोल फ्री नंबर 1800212884444 का शुभारंभ किया गया।
- प्रदेश के 7,500 पैक्स में फर्टिलाइजर आदि की खरीद के लिये क्रेडिट लिमिट को बढाकर 10 लाख रुपए किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।
- प्रदेश भर में सहकारी बैंकों की नई शाखाएँ खोलने के लिये मैपिंग कराने हेतु सहकारिता विभाग को निर्देशित किया गया है।
- पैक्स के माध्यम से 300 से अधिक ई-सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके माध्यम से कृषि एवं कृषि व्यवसाय में अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। कृषि संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएँ जैसे- बीज, खाद, यंत्र, कीटनाशक औषधि उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :

- पैक्स के माध्यम से सदस्यों को कृषि उद्योग, कृषि उपज एवं कुटीर उद्योग और रोजमर्रा की चीज़ों को विक्रय कराने का प्रबंध किया जाएगा।
- बी-पैक्स का अर्थ साधन सहकारी अभियान से है। बी-पैक्स (साधन सहकारी अभियान) सहकारी समिति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पछाड़ा

चर्चा में क्यों ?

- 4 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उत्तर प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी पकड़ी है। 2019 से 2023 के बीच पाँच साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2017 के बीच 17 वर्षों में जितना विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया, उसका करीब चार गुना वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच महज पाँच वर्षों में आया है।
- उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 2000 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में केवल 3000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, जबकि 2019 से जून 2023 के बीच करीब 11 हज़ार करोड़ रुपए सीधे विदेश से निवेश किये गए।
- अक्तूबर 2019 से जून 2023 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश से ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं।
- उत्तर प्रदेश ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, छत्तीसगढ़ सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक रफ्तार को देखते हुए इस साल उत्तर प्रदेश के देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होने की उम्मीद है।
- निवेश किसी भी राज्य की प्रगति और सामाजिक व राजनीतिक माहौल का सूचकांक माना जाता है। जिस राज्य की छवि कम अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की होगी, वहाँ निवेश की रफ्तार तेज़ व ज़्यादा होती है। विदेशी कंपनियों से आने वाले निवेश के मामले में ये मानक और भी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं।
- इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने से ही एफडीआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पिछले 17 साल में केवल 3018 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। वर्ष 2014-15 में 679 करोड़ रुपए, 2015-16 में 524 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 50 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। वर्ष 2000 से 2014 के बीच 14 साल में भी करीब 1800 करोड़ रुपए ही एफडीआई के रूप में आए।

उत्तर प्रदेश के तीन शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के तीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देशभर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।
- इस शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 50 हज़ार रुपए नकद, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया।
- इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये उत्तर प्रदेश के तीन शिक्षकों को चुना गया था, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में मेरठ के के. एन. इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर पांडा, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और फतेहपुर की आशिया फारूकी शामिल हैं।
- विदित है कि चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदशहर जनपद का नाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सुर्खियों में लाने का काम किया है। शिवकुमार जनता इंटर कॉलेज बुलंदशहर का पहला हाईटेक स्कूल है और यहाँ बेटियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्कूल का योगदान पूरे बुलंदशहर में सबसे बेहतर है। विद्यालय में आर्यभट्ट खगोलीयशाला स्थापित की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को खगोलीय ज्ञान की जानकारी दी जाती है।
- फतेहपुर नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अस्ती की शिक्षिका आशिया फारूकी ने नवाचार के दम पर विद्यालय का कायाकल्प किया। अकेले पाँच कक्षाओं का संचालन कर ज्वायफुल लर्निंग से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की। इसका परिणाम है कि तीन वर्ष में स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या 250 पहुँच गई।
- राष्ट्रीय शिक्षक दिवस:
  - वर्ष 1962 से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य भारत में स्कूल अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं और प्रोफेसरों सहित अन्य शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना है।

- भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्रों के उत्सव के अनुरोध की प्रतिक्रिया में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था।

- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार:
  - राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का जश्न मनाना तथा उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है।
  - ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
  - पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण-पत्र एवं 50,000 रुपए की नकद राशि शामिल है।
  - इस वर्ष पुरस्कार के दायरे में स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है।

प्रदेश के 94 शिक्षकों को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 94 शिक्षकों को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिये राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षक शामिल हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों के 02 लाख 09 हज़ार से अधिक अध्यापकों को टैबलेट वितरण, 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट लैब्स की स्थापना की कार्यवाही तथा 880 आई.टी.सी. लैब्स का शुभारंभ भी किया।

नमामि गंगे ने मेरठ में सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और अन्य अवसंरचना के विकास के लिये एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स मेरठ एसटीपी प्रा. लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के अंतर्गत इस परियोजना की कुल लागत 369.74 करोड़ रुपए है और इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- एनएमसीजी ने 220 एमएलडी की कुल क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण करने के लिये परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन (आई एंड डी) संरचनाओं का विकास, आई एंड डी नेटवर्क बिछाना, 15 वर्षों के लिये परिचालन एवं रखरखाव सहित सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि जैसे अन्य कार्य भी शामिल हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य मेरठ शहर में मौजूदा सीवेज समस्याओं और इसके कारण काली नदी में सीवेज प्रदूषण की समस्या का समाधान करना भी है।
- इस परियोजना के पूरा होने के बाद मेरठ शहर से काली नदी (पूर्व) में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन नहीं होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी।
- काली (पूर्व) कन्नौज के समीप गंगा नदी से मिलती है और इस परियोजना के पूरा होने से गंगा नदी के प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।
- इस समझौते पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधीक्षण अभियंता, एसके बर्मन, मयंक अग्रवाल, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स मेरठ एसटीपी प्राइवेट लिमिटेड और विनोद कुमार, निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी ने जी. अशोक कुमार, एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

उत्तर प्रदेश के आठ ज़िले सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट वाले बनेंगे

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आठ ज़िलों को सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। इस वर्ष तक ये सभी ज़िले शत-प्रतिशत डिजिटल पेमेंट में पारंगत हो जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इन सभी आठ ज़िलों को अलग-अलग बैंकों ने गोद लिया है। इनमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महराजगंज, देवरिया और बहराइच शामिल हैं। आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय इन सभी ज़िलों की सीधी मॉनीटरिंग कर रहा है।
- सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट के लिये चुने गए ज़िले फतेहपुर की ज़िम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया को कन्नौज, केनरा बैंक को अमरोहा, यूनियन बैंक को वाराणसी, पीएनबी को शामली, स्टेट बैंक आफ इंडिया को महराजगंज, सेंट्रल बैंक को देवरिया और इंडियन बैंक को बहराइच का उत्तरदायित्व दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जहाँ की लगभग 23 फीसदी आबादी पीएम सुरक्षा बीमा योजना से कवर है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश के 1.75 करोड़ लोग कवर हैं, जो देश में दूसरे स्थान पर है।
- अप्रैल से जून के बीच क्रमश: 10.83 लाख और 28.43 लाख लोगों को दोनों योजनाओं के अंदर कवर किया गया है। प्रदेश के लगभग पाँच करोड़ लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किये जा चुके हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बीमा कवर वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई-बस

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिये प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने जा रही हैं। यह बसें पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग इसके लिये प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- बड़े शहरों में 150-150, मध्य शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाए जाने की योजना है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
- केंद्र सरकार की फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में मौजूदा समय 740 छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं। फेस-दो में करीब 300 बसें और ली जानी थीं, लेकिन सरकार ने पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। इसके चलते फेम इंडिया फेस-दो में अब नई बसें नहीं खरीदने पर मंथन चल रहा है। नगर विकास विभाग अब पीएम ई-बस सेवा में नई बसों की मांग करेगा।
- शासन स्तर पर तैयार किये जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य के बड़े शहरों खासकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 150-150 और नई बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- आगरा, झांसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद व गौतमबुद्धनगर में 100-100 बसें चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- इसके अलावा अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर व सहारनपुर में 50-50 बसें चलाने की योजना है।

उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू होगा ई-ऑफिस

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से करेगी, इसलिये सभी ज़िलों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- शासन स्तर पर यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब ज़िलों व मंडलों में स्थित सरकारी दफ्तरों में भी यह व्यवस्था लागू होगी।
- हाल ही में कन्नौज ज़िले में पूरी तरह ई-ऑफिस लागू हो चुका है और उसी के अनुसार वहाँ कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट हो रहा है।
- अब ज़िलों में सभी कर्मचारियों के ई-मेल आईडी जेनरेट कराने का काम शुरू होगा। उसके बाद उनका प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा मंडल स्तर पर काम कर रहे सभी सरकारी विभागों में भी यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे एक तरह से सरकारी काम में पेपरलेस व्यवस्था लागू होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, ज़िलों, मंडलों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिये थे। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से यह काम शुरू हुआ।

नोट :

- हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने इसे सभी ज़िलों व मंडलों में लागू करने को कहा है। इससे ज़िलों के कलेक्ट्रेट व अन्य सरकारी कार्यालयों में पत्रावलियाँ डिजिटाइज होंगी। इसके ज़रिये सरकारी कार्मिकों के काम की भी निगरानी होगी।
- ज़िलाधिकारी किसी भी पत्रावली की मॉनीटरिंग कर सकेंगे और इससे ज़िलों से शासन को जाने वाली पत्रावलियों का काम तेज़ी से हो सकेगा।
- सचिवालय के 93 विभागों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू हो चुकी है। ई-ऑफिस माध्यम से अब तक 8654 फाइल जारी हो चुकी हैं। 150 विभागाध्यक्ष कार्यालय में से अब तक 46 में ई-ऑफिस लागू हो चुका है और इसी के अनुरूप काम हो रहा है।
- पुलिस से जुड़े 90 कार्यालयों व विभागों में केवल 35 में ही यह व्यवस्था लागू हो पाई है, जिसमें अब तक 8181 फाइल जारी हो चुकी हैं। अभी किसी मंडल स्तर पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।
- ई-ऑफिस क्या है?
  - ई-ऑफिस यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का एक माध्यम है।
  - ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के ज़रिये जहाँ सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी।

हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, देश में बुलंदशहर पहले व बरेली तीसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश की रफ्तार बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज है। देश में बुलंदशहर पहले व बरेली तीसरे स्थान पर हैं।

प्रमुख बिंदु

- जल जीवन मिशन की अगस्त माह की प्रगति के आधार पर केंद्र ने देश के 218 ज़िलों की रैंक जारी की है।
- ओवरहेड टैंक बनाने से लेकर घरों तक पानी की आपूर्ति करने की प्रगति के आधार पर केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय यह रैंक जारी करता है।
- जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति करने में पहले पायदान पर बुलंदशहर काबिज है, जबकि बरेली ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

- बुलंदशहर में ओवरहेड टैंक का निर्माण भी तेजी से हुआ है। साथ ही घरों में पानी का कनेक्शन देने में आगे है। बुलंदशहर ने करीब 98 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- बरेली की 877 ग्राम पंचायतों में ओवरहेड परियोजना तैयार की जा रही है। वहीं1867 ग्राम पंचायतों में पानी की आपूर्ति की जानी है जबकि 433 ग्राम पंचायतों में पेयजल पहुँचा दिया गया है।
- मुजफ्फनगर को चौथा स्थान मिला है। बरेली मंडल का बदायूं ज़िला करीब 87 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करके 5वें स्थान पर है।
- लखीमपुर खीरी को जल जीवन मिशन में देश में 42वीं रैंक मिली है, जबकि प्रदेश में 25वीं रैंक है। खीरी ने करीब 68 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है।
- जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष 50 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के 26 ज़िले शामिल हैं, जबकि देश के शीर्ष 10 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के सात ज़िले शामिल हैं।
- देश में शीर्ष दस ज़िले: बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), साउथ सलमारा मनकचर (असम), बरेली (उत्तर प्रदेश), मुजफ्फनगर (उत्तर प्रदेश), बदायूं (उत्तर प्रदेश), मुंगेली (छत्तीसगढ़), तिरुपत्तूर (तमिलनाडु), चंदोली (उत्तर प्रदेश), कन्नौज (उत्तर प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

बुंदेलखंड में बनेगा नोएडा जैसा औद्योगिक शहर

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- झाँसी-ग्वालियर मार्ग पर बनने वाली इस औद्योगिक टाउनशिप के लिये 33 राजस्व गाँवों की 35 हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस ज़मीन के अधिग्रहण में 6312 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों बाद नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

- वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत झाँसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के माध्यम से कुल 14 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है।
- यह औद्योगिक शहर झाँसी ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 27 से जालौन से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ेगा।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई

चर्चा में क्यों?

- 13 सितंबर, 2023 को राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिये नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये हैं, जिसके अंतर्गत अब स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी।

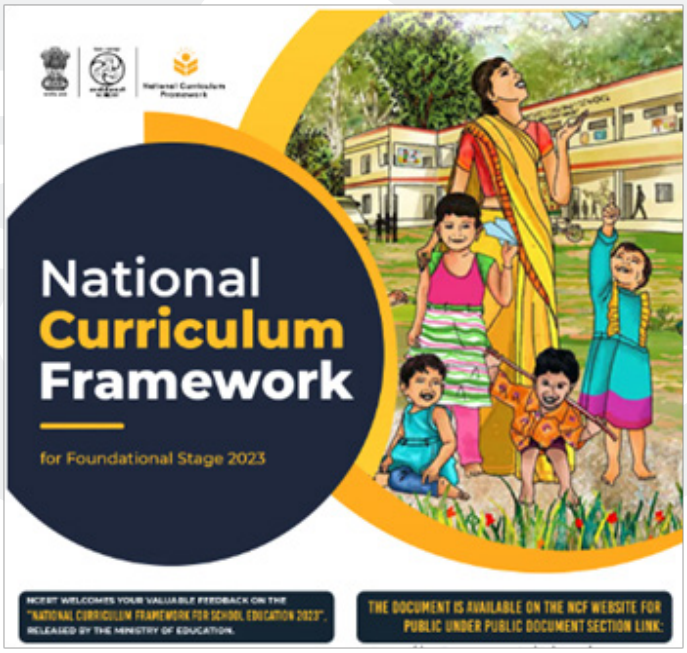

प्रमुख बिंदु

- नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे में कक्षाएँ लगाने की संस्तुति की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे।
- दो शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय-सीमा 45 से घटकर 35 मिनट की जाएगी, जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी।
- प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषयों गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेज़ी व अंग्रेज़ी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के ज़रिये पढ़ाया जाएगा।

लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल तीन यूनिटी मॉल देने की घोषणा के बाद इस पर काम शुरू हो गया है।

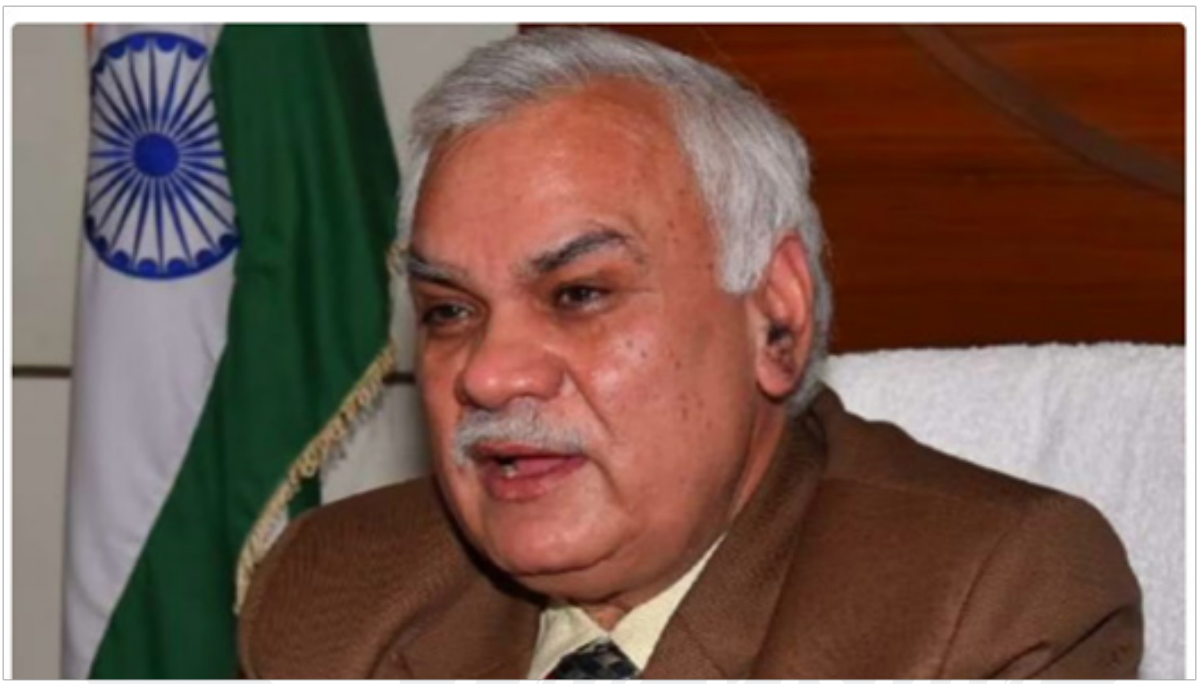

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वाराणसी में प्रस्तावित यूनिटी मॉल के संबंध में भूमि के चिन्हांकन के निर्देश दिये हैं, जबकि आगरा में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।
- मॉल में आने वाले लोगों को खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये फूडकोर्ट भी खुलवाए जाएंगे।
- विविद है कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल की स्थापना किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- लखनऊ में यूनिटी मॉल अवध शिल्प ग्राम में बनेगा, लेकिन उससे पहले वहाँ वर्तमान में मौजूद 35 वातानुकूलित शोरूम में मॉल शुरू कर दिया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने कहा कि द्वितीय चरण में अवध शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल की डिजाइन व डीपीआर को आवास विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- यूनिटी मॉल में राज्यों द्वारा अपने ओडीओपी उत्पादों, जीआई उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों व अन्य राज्यों के ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी तथा बिक्री की व्यवस्था की जाएगी।
- यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी प्रयासों को बढ़ावा देना और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद एवं स्थानीय रोज़गार सृजन करना है।
- यूनिट मॉल के संचालन के संबंध में एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी। कमेटी में आवास विकास और एमएसएमई विभाग को शामिल किया जाएगा।

आयुष्मान भव: अभियान

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से आयुष्मान भव: अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में इसका शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 17 सितंबर से 2 अक्तूबर के बीच चलने वाले इस अभियान का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू गाँवों को आयुष्मान बनाने का प्रयास है।
- प्रत्येक चिह्नित मरीज़ का इलाज शुरू कराया जाएगा, जिसमें टीबी, कैंसर से लेकर डायबिटीज और हाइपर टेंशन की जाँच होगी। गाँव के बच्चों का शत-प्रतिशत नियमित टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- आयुष्मान कार्ड के ज़रिये उन्हें पाँच लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं आभा आईडी बनने से लोगों को अपने इलाज और जाँचों का पुराना रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

- प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया इसके साथ ही डायबिटीज और हाइपर टेंशन के अलावा ओरल, ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराई जाएगी, ताकि ऐसे मरीज़ों का इलाज शुरू कराया जा सके। वहीं प्रति हज़ार लोगों में से 30 लोगों की टीबी की जाँच कराई जाएगी।

हिन्दी दिवस के अवसर पर 16 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2023 को लखनऊ में 'उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स' की ओर से हिन्दी दिवस पर आयोजित 'अपनी हिन्दी अपना भारत' सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन में 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा 16 वरिष्ठ साहित्यकारों, लेखक, गीतकार, पत्रकारों को सम्मानित किया गया।
- सम्मान पाने वालों में पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, डॉ. राम बहादुर मिश्रा, विनोद मिश्रा, महेंद्र भीष्म, विनोद शंकर शुक्ल, डॉ. ओम प्रकाश सिंह, केशव प्रसाद वाजपेयी, डॉ. सोनरूपा विशाल, विनीता मिश्रा, गजेंद्र प्रियांशु, अलंकार रस्तोगी, नीरज अरोड़ा, दयानंद पांडेय, राजकुमार सिंह, जगदंबा प्रसाद और डॉ. अर्चना सतीश शामिल रहीं।
- इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम अपने प्रदेश की संस्कृति को विदेश तक ले जा रहे हैं और पहले चरण में कोरिया से शुरू किया है।

आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन की मासिक टॉप और बॉटम 10 ज़िलों की रैंकिंग जारी

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को जनसुनवाई समाधान प्रणाली, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की अगस्त माह की टॉप और बॉटम 10 ज़िलों की रैंकिंग मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के पैमाने पर जनसुनवाई में प्रदेश में अमेठी व कन्नौज सबसे बेहतर रहे हैं जबकि बागपत व गोरखपुर के ज़िलाधिकारियों की कार्यशैली सबसे खराब पाई गई है।
  - टॉप और बॉटम 10 ज़िलाधिकारी : आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के कार्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 ज़िलाधिकारियों में क्रमश: अमेठी, कन्नौज, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, महोबा, मिर्जापुर, हापुड़ और भदोही हैं। वहीं लिस्ट में बॉटम 10 में बागपत, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी हैं।
- इसी तरह अलीगढ़ व श्रावस्ती सबसे अच्छे पुलिस अधीक्षकों वाले ज़िले पाए गए हैं, जबकि बरेली एसएसपी और लखनऊ पुलिस आयुक्त की कार्यशैली सबसे खराब पाई गई है।
  - टॉप और बॉटम 10 पुलिस आयुक्त, एसएसपी और एसपी : जारी लिस्ट में प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य करने वाले पुलिस आयुक्त, एसएसपी और एसपी में क्रमश: अलीगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, हमीरपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, कासगंज, चित्रकूट, भदोही और हाथरस हैं। इसी प्रकार बॉटम 10 में क्रमश: बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, झाँसी, अयोध्या, एटा, हापुड़, आजमगढ़ और संत कबीर नगर के पुलिस अधिकारी हैं।
- इसके अलावा लिस्ट में सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली प्रदेश की तहसीलों को भी शामिल किया गया है। तहसीलों के कार्यों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ये लिस्ट तैयार हुई है।
  - टॉप और बॉटम 10 तहसीलें : टॉप 10 तहसीलों में अलीगढ़ की कोल, जौनपुर की केराकत और बदलापुर, श्रावस्ती की इकौना, प्रयागराज की सदर, बागपत की बड़ौत, अलीगढ़ की अतरौली, बुलंदशहर की स्याना, जालौन की उरई और अमरोहा की हसनपुर तहसील शामिल हैं। इसी प्रकार खराब प्रदर्शन वाली बॉटम 10 में क्रमश: रामपुर की बिलासपुर, कन्नौज की तिर्वा और छिबरामऊ, रामपुर की मिलक, हापुड़ की धौलाना, हाथरस की हाथरस, संत कबीरनगर की खलीलाबाद, खीरी की धौरहरा, कन्नौज की कन्नौज और रायबरेली की ऊँचाहार तहसील शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप जीती

चर्चा में क्यों ?

- 16 सितंबर, 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित डॉ. बी सी राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 2-1 गोल से हराया।
- उत्तर प्रदेश के लिये लखनऊ के निरंजन जंगशाही ने 31वें और कुलदीप सिंह ने 80वें मिनट में गोल दागे। पश्चिम बंगाल की ओर से एकमात्र गोल तनवीर डे ने 70वें मिनट में किया।
- इस टूर्नामेंट में लखनऊ मंडल की ओर से निरंजन जंगशाही ने सबसे ज्यादा आठ गोल किये। वह लखनऊ के सहारा क्लब के लिये खेलते हैं।

मुख्यमंत्री ने गीडा में किया तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि गीडा से लेकर धुरियापार तक औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है। धुरियापार में 5000 एकड़ में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोज़गार और नौकरी उपलब्ध हो सकेगी।
- विदित है कि पिछले छह साल में गीडा में निवेश और रोज़गार की स्थिति में बदलाव हुआ है। उद्योग धंधों पर पूर्वांचल से युवाओं का पलायन रोका गया है।
- गीडा के उद्घाटन अवसर पर 97 उद्यमियों को भूमि का आवंटन पत्र बाँटा गया है। अब यहाँ फैक्ट्रियों का काम शुरू होगा। इन फैक्ट्रियों में 1000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 5000 से अधिक युवाओं को रोज़गार मिलेगा।
- ज्ञातव्य है कि 10 से 12 फरवरी, 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अकेले गोरखपुर को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले।
- 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर एक करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोज़गार मिलने की संभावना है। गीडा में 102 नए उद्योगों की स्थापना के लिये आशय पत्र के वितरण का कार्य इसी संभावना को आगे बढ़ाएगा।

उत्तर प्रदेश में अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक ज़ोन

चर्चा में क्यों?

- 18 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेंगे। ये परिक्षेत्र युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर व साक्षरता दर के आधार पर तय होंगे।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पहले चरण में नोएडा, लखनऊ में यह विशेष शिक्षा परिक्षेत्र आकार ले सकता है।
- इस योजना के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिये शैक्षिक संस्थाओं की अनुपयोगी ज़मीन भी चिन्हित की जा रही है, जिसका उपयोग इस एसइजेड के लिये हो सकता है।

- यह एजूकेशन क्लस्टर बहुआयामी शिक्षा, शोध व कौशल विकास पर काम करेंगे। इसके लिये अब विस्तृत कार्ययोजना बन रही है और उसके बाद विशेष शैक्षिक ज़ोन के लिये लोकेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिये अमेरिकन सलाहकार कंपनी डेलायट की विभिन्न सेक्टरों में दी गई रिपोर्ट को विभागों के सहयोग से लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अब उच्च व तकनीकी शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय, निजी निवेशकों व शैक्षिक संगठनों से आगे की योजना पर बैठकें शुरू हो गईं हैं।
- डेलायट का कहना है कि शैक्षिक जगत को उद्योग से सीधा जोड़कर राज्य के लाखों स्नातकों को रोज़गार दिलाया जा सकता है। इसके लिये विशेष शिक्षा क्षेत्र, निजी विश्वविद्यालयों को निवेश के लिये प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश, दिलाने जैसे काम किये जाने बहुत जरूरी हैं।
- विदित है कि डेलायट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10851 छात्रों को निजी कंपनियों में रोज़गार मिला है। यह साल 2022 से 10 प्रतिशत ज्यादा है।
- पालीटेक्निक कॉलेजों में 365340 सीटें भरी हैं, इसमें पिछले साल के मुकाबले 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। छह पालीटेक्निक पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं। राजकीय पालीटेक्निक में शुरू हुए नये पाठ्यक्रमों के लिये 1575 सीटें हैं।

बरेली के इत्र से महकेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21-25 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें बरेली का बना इत्र अपनी सुगंध बिखेरेगा।

प्रमुख बिंदु

- बरेली के इत्र को ट्रेड शो के हॉल नंबर 15 में विशेष स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि यह इत्र यूरोपीय देशों के साथ-साथ अमेरिका में भी तारीफ बटोर चुका है।

- जरी और सुरमे के लिये पूरी दुनिया में मशहूर बरेली अब सुगंधित तेलों, इत्र और परफ्यूम के लिये भी जाना जाने लगा है। बरेली के युवा यूरोप और अमेरिका तक सुगंधित तेलों का निर्यात कर रहे हैं।
- इसकी बड़ी उपलब्धि यह है कि केंद्र सरकार ने बरेली की एरोमेटिक एंड एलाइड केमिकल्स को एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता दे रखी है।
- आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद फ्राँस से परफ्यूमरी का कोर्स करने वाले गौरव मित्तल इस समय अमेरिका और यूरोप में निर्यात कर रहे हैं।
- यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी उनकी कंपनी को मुख्य पवेलियन में विशेष स्थान दिया गया है। इसके जरिये विश्व बाज़ार को यह दिखाने का अवसर मिला है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्राकृतिक इत्र और आवश्यक तेल उत्तर प्रदेश और वह भी बरेली में बनाए जा सकते हैं।
- गौरव मित्तल ने बताया कि हमारी कंपनी सुगंधित और संबद्ध रसायन, प्राकृतिक और जैविक तेलों की निर्यातक है, जो वर्ष 1977 से व्यवसाय में हैं। कंपनी के तहत लॉ मोंक ब्रांड स्थापित किया गया है जो केवल 100 फीसदी प्राकृतिक, जैविक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इत्र कारोबार के लिये गौरव मित्तल का सम्मान कर चुके हैं। गौरव किसानों को आगे बढ़ाने के लिये मेंथा आयल, लेमन ग्रास आयल, रोज आयल आदि की खेती करवा रहे हैं।

लखनऊ की आस्था स्ट्रांग वुमेन और आर्य बने स्ट्रांग मैन

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के टाटानगर (जमशेदपुर) में हुई सीनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में लखनऊ की आस्था स्ट्रांग वुमेन और आर्य स्ट्रांग मैन बने।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश टीम की महिला सदस्य आस्था सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्ट्रांग वुमेन का खिताब जीता, वहीं आर्य सिंह ने पुरुषों में यह उपलब्धि हासिल करते हुए स्ट्रांग मैन का खिताब अपने नाम किया।

नोट :

- सीनियर वर्ग व सब जूनियर वर्ग में उत्तर प्रदेश के निराले खान को 'स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया' का खिताब दिया गया।
- विदित है कि 9 से 12 सितंबर के बीच सीनियर एवं सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
- इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने कुल 31 पदक जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इसमें 15 स्वर्ण, 10 रजत व 6 काँस्य पदक शामिल हैं। इसमें लखनऊ के मुकुल चौरसिया और सविता सिंह ने काँस्य पदक जीते।

कवि अरुण कमल को मिलेगा 'निराला स्मृति सम्मान'

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष का 'निराला स्मृति सम्मान' समकालीन कविता के कवि अरुण कमल को दिये जाने की घोषणा की गई है।

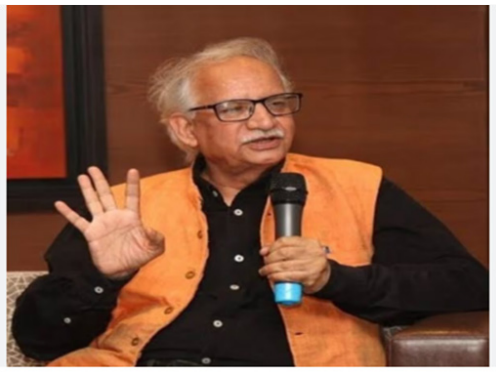

प्रमुख बिंदु

- कवि अरुण कमल को यह सम्मान छायावादी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की पुण्यतिथि पर 15 अक्तूबर को निराला स्मृति आयोजन के दौरान दिया जाएगा।
- यह सम्मान महाकवि निराला की चेतना, विचारधारा और उनकी रचनात्मक परंपरा से जुड़ने वाले रचनाकार को दिया जाता है।
- निराला के निमित्त संस्था के अध्यक्ष व महाकवि निराला के प्रपौत्र विवेक निराला ने बताया कि इससे पूर्व यह सम्मान कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मुद्गल को प्रदान किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय हे कि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (21 फरवरी, 1896 -15 अक्तूबर, 1961) हिन्दी कविता के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं किंतु उनकी ख्याति विशेषरुप से कविता के कारण ही है।
- 1920 ई के आसपास उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी पहली रचना जन्म भूमि पर लिखा गया एक गीत था। 1916 ई. में उनके द्वारा लिखी गई 'जूही की कली' 1922 ई. में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत ही लंबे समय तक का प्रसिद्ध रही।
- उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह जैसे अनामिका (1923), परिमल (1930), तुलसीदास (1939), कुकुरमुत्ता (1942), गीत कुंज (1954) इत्यादि हैं।

20वाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला का लखनऊ में होगा आयोजन

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकरी के अनुसार 20वाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित होगा।

प्रमुख बिंदु

- 11 दिवसीय पुस्तक उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे पुस्तक विमोचन, लेखकों से मिलें, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के कार्यक्रम होंगे।
- 20वाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला 'ज्ञान कुंभ'की थीम पर होगा, जिसमें प्रवेश नि:शुल्क रखा गया है और पुस्तकों पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- आयोजक मनोज चंदेल ने बताया कि इस पुस्तक मेले ने देश के शीर्ष 10 पुस्तक मेलों में अपना स्थान बनाया है।
- मेले में इस वर्ष दिल्ली, मुंबई, रायपुर, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, रायपुर, गुजरात, राजस्थान के सरकारी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बड़ी संख्या में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भाषा के प्रकाशक एवं वितरक भाग लेंगे।

आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ चलाएंगी औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2023 को कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन चलाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज़ों तीमारदारों व अन्य के लिये कैंटीन चलाने की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ अब औद्योगिक संस्थानों में भी कैंटीन चलाएंगी।
- इसके लिये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीसीडा) और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच करार होगा। इस योजना के तहत यूपीसीडा स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कैंटीन के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराएगी।
- यूपीसीडा और आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 25 ज़िलों में 150 क्लस्टर कैंटीन खोली जाएंगी। ये कलस्टर कैंटीन ब्रांडेड फूडचेन की तर्ज़ पर होंगे, जहाँ पर दीदियों के हाथ से बने स्पेशल खाद्य पदार्थों की बिक्री होगी।
- एक क्लस्टर कैंटीन में 8 से 10 दीदियों को रोज़गार मिलेगा। ये कैंटीन शहरों में खुलेंगी, जहाँ पर लोगों का अधिक आना-जाना रहता है।
- संचालन की पूरी ज़िम्मेदारी दीदियाँ संभालेंगी। इन कैंटीन में उद्योगों में कार्यरत् कार्मिकों व श्रमिकों को उचित मूल्य पर घर जैसे स्वाद में खाने-पीने की वस्तुएं मिलेंगी।
- आजीविका मिशन की निदेशक सी. इंदुमति के मुताबिक कानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कैंटीन जल्द खुल जाएगी। इसके अलावा अलीगढ़, वाराणसी, मथुरा आदि शहरों के इंडस्ट्रियल एस्टेट में कैंटीन खोले जाने के लिये अध्ययन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो' के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर, 2023 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है।
- इस ट्रेड शो में 2,000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नए उद्यमियों तक, विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध हैं।
- विश्व के विभिन्न हिस्सों से 66 देशों के 400 से अधिक बायर्स भी इस ट्रेड शो में भाग ले रहे हैं।
- प्रदेश के 54 जी.आई. प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी का भी इस ट्रेड शो में आयोजन किया जा रहा है।
- यह ट्रेड शो सभी सेक्टरों के उत्पाद को प्रदर्शित करेगा। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई-कॉमर्स, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ डेयरी प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल के उत्पाद सहित विभिन्न सेक्टर की प्रदर्शनियाँ इस उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का अहम हिस्सा हैं।
- हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ-साथ राज्य के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

नोट :

- प्रदेश ने पिछले 06-07 वर्षों में देश के आर्थिक विकास में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। राज्य की जी.डी.पी., जो वर्ष 2016-17 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए थी, वह वर्ष 2022-23 में करीब 22 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।
- 96 लाख से अधिक एम.एस.एम.ई. इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले नंबर पर है।

प्रधानमंत्री ने काशी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा पहला स्टेडियम है।
- वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा।
- आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी, राजातालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और यह 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा।
- इस स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की लाइट, घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और अगले हिस्से पर बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिज़ाइन विकसित किये गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी किया गया।
- प्रधानमंत्री काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-2023' के अंतर्गत विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।
- इन संस्कृति कर्मियों को सम्मानित करने का अभिनव कार्यक्रम पहली बार हुआ है। इसमें लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लिया।
- प्रधानमंत्री ने 15 अक्तूबर से 05 नवंबर, 2023 तक आयोजित होने वाले 'काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं' हेतु पोर्टल तथा क्यू-आर कोड का उद्घाटन भी किया।

लखनऊ का एबीसी केंद्र बनेगा देश के लिये मॉडल

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर विकास विभाग ने भारत सरकार की संस्था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) के साथ पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र चलाने के लिये अनुबंध किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहाँ के 17 नगर निगमों में एबीसी केंद्र के निर्माण की कार्ययोजना चल रही है।
- इसके माध्यम से राजधानी में बने एबीसी केंद्र को नवीनतम तकनीक से पूर्ण कर पूरे भारत के लिये मॉडल बनाया जाएगा।
- देश में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, जहाँ की प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से ऐसे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है।
- बापू भवन सचिवालय स्थित नगर विकास विभाग के विशेष सचिव के कार्यालय में यह अनुबंध हुआ।

लखनऊ में होंगे राज्य ओपेन पैरा खेल

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स की गाज़ियाबाद में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन तीन दिसंबर को दिव्यांग दिवस पर राज्य ओपेन पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप कराएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों की 'सेंड ऑफ सेरेमनी' भी लखनऊ में होगी।
- फरवरी में राज्य पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य पैरा एथलेटिक्स या पावरलिफ्टिंग की चैंपियनशिप का आयोजन भी होगा।
- बैठक में लखनऊ में होने वाले कार्यक्रमों की आयोजन समिति का चेयरमैन लखनऊ की डॉ. सुधा वाजपेयी को बनाया गया है।
- वहीं यूपी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ। इसमें गाज़ियाबाद के कविंदर चौधरी को एक बार फिर अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सचिव डा. सुधा वाजपेयी को संयुक्त सचिव चुना गया है।

लखनऊ की पूर्णिमा को मिला विद्यावती स्मृति सम्मान

चर्चा में क्यों?

- 24 सितंबर 2023 को लखनऊ साहित्यिक संस्था सर्वजन हिताय साहित्यिक समिति का सारस्वत सम्मान समारोह प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें लखनऊ की पूर्णिमा को 'विद्यावती स्मृति सम्मान' प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में रायबरेली के डॉ. रामेंद्र पांडेय को 'साहित्य निधि सम्मानोपाधि' से सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत दो हज़ार पाँच सौ रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृतिचिह्न प्रदान किया गया।
- सीतापुर के हिन्दी विद्वान डॉ. अरुण त्रिवेदी को पाँच हज़ार रुपए धनराशि के 'डॉ. अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- रायबरेली के डॉ. राजेंद्र को साहित्य निधि सम्मान दिया गया।
- लखनऊ के ही डॉ. अशोक शर्मा को 'कृष्ण सहाय निगम स्मृति सम्मान' तथा अंबेडकर नगर के भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को 'राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- हरदोई के युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को 'पंडित रामगुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्यत मंगलकामना अलंकरण सम्मान' दिया गया।
- मोटोजीपी बाइक रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) ग्रेटर नोएडा में हुई संपन्न।

मोटोजीपी बाइक रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) ग्रेटर नोएडा में हुई संपन्न

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को मोटोजीपी बाइक रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) ग्रेटर नोएडा में फाइनल मुकाबले के साथ संपन्न हुई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मोटोजीपी रेस मूनी वी आर46 रेसिंग टीम के मार्को बेज्जेच्ची ने अपने नाम दर्ज की। जे. मार्टिन ने दूसरा और आर. क्वाटरो ने तीसरा स्थान हासिल किया।
- विदित है कि बीआईसी में 22 सितंबर से 24 सितंबर तक मोटोजीपी रेस आयोजित हुई। एशिया में पहली बार भारतीय सरजमीं पर मोटरबाइक रेस (मोटोजीपी) का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 41 टीम, 82 राइडर्स (चालक) ने हिस्सा लिया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पोडियम एरिया में शीर्ष 3 राइडर्स को ट्रॉफी प्रदान की।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस के विजेता बेज्जेच्ची को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।

आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को मिले दो अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दो दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को दो अवॉर्ड प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा और व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवाओं के लिये राज्य एजेंसी (SACHIS) की सीईओ संगीता सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया।
- प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिये उत्तर प्रदेश को यह अवॉर्ड प्रदान किया गया है।

नोट :

- उत्तर प्रदेश को पहला आयुष्मान अवॉर्ड पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिये, जबकि दूसरा आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करने के लिये मिला है।
- आभा स्कैन, यानी आभा एप्लीकेशन के ज़रिये मरीज़ आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है।
- आशियाना के लोकबंधु अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आभा लिंक के तहत देश में तीसरा पुरस्कार मिला है। लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- राजधानी दिल्ली में यह आयोजन पीएमजेएवाई के पाँच वर्ष पूरे होने पर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
  - भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करना है।
  - यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुविधाजनक बनाने और भारत के लोगों के लिये समग्र स्वास्थ्य देखभाल अनुभव को बेहतर बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

- 27 सितंबर, 2023 को इंदौर में स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान पर आने पर पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- सरकार ने 25 अगस्त को भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता (आईएसएसी) की घोषणा की थी। देश की सौ स्मार्ट सिटी के बीच विभिन्न श्रेणियों में यह प्रतियोगिता थी।
- समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात व स्मार्ट सिटी मिशन निदेशक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया।

नोट :

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं।
- सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष तीन राज्यों में चुना गया है। इसके अलावा आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है।
- इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल हुए हैं।
- नॉर्थ ज़ोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर वन पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है।
  - 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान
  - कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण कार्य के लिये तीसरा
  - इकॉनमी श्रेणी में रोज़गार ट्रेनिंग सेंटर कार्य के लिये लखनऊ को तृतीय स्थान। लखनऊ स्मार्ट सिटी स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता, स्मार्ट प्रशासन आदि शामिल हैं।
- स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हासिल किया 100% ओडीएफ प्लस कवरेज

चर्चा में क्यों?

- 28 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अंतर्गत 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँवों, यानी मिशन के चरण II के तहत 100 % गाँवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ओडीएफ प्लस गाँव वह है, जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखा है।
- अभी तक, देश भर में 4.4 लाख (75%) गाँवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- चालू वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी, 2023 तक उत्तर प्रदेश में केवल 15,088 गाँव थे, जिन्हें ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था। केवल 9 महीने की छोटी-सी अवधि में, राज्य ने मिशन मोड में ओडीएफ प्लस हासिल करने के लिये प्रयास किये।
- पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गाँवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया और इस त्वरित गति के परिणामस्वरूप ओडीएफ प्लस की समयबद्ध उपलब्धि हासिल हुई।
- पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण और साइट पर सहायता, तेजी से कार्यान्वयन के लिये प्रमुख कारक थे।
- 95,767 ओडीएफ प्लस गाँवों में से 81,744 गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस महत्त्वाकांक्षी गाँव हैं, 10,217 गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस उभरते गाँव हंट और 3,806 गाँव ओडीएफ हैं।
- ओडीएफ प्लस मॉडल गाँव वह है, जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखे हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है तथा दृश्य स्वच्छता का निरीक्षण करता है, यानी न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं करना और जहाँ ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित किये जाते हैं।